डेढ़ करोड़ में से केवल 27 लाख रुपये खर्च किये। जब तक उपयोग करने का, यूटीलिटी सर्टीफिकेट जिसको कहते हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक धन निर्मुक्त करना मुश्किल है और इसीलिए सात करोड़ को काटकर एक करोड़ किया गया है क्योंकि आम तौर पर इस तरह के कार्यक्रम में राज्य सरकारों की दिलचस्पी कम रहती है। फिर भी मुजफ्फरपुर और पोनिया जिले में फ्लड प्रूफिंग का कार्यक्रम चल रहा है और फ्लड प्रूफिंग के काम को आगे बढ़ाने और मानिटरिंग के लिए अभी एक मीटिंग वहां के ऐक्सपर्ट्स की बुलाई गयी है और हम समझते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। रह गयी बात नेपाल से बहने वाली तीन-चार नदियों की, उनके बारे में नेपाल सरकार से हम लोगों ने तटबंध को और ऊंचा बढ़ाने की बात की थी, खास तौर से वहां के जल संसाधन मंत्री से। इन्होंने भी इस सम्बन्ध में सहमति जताई है। कुछ नदियां जो तिब्बत से बहकर आती है, उसके बारे में चीन से उनकी बातचीत हुई होगी और वह हमारे मंत्रालय और सरकार का विषय नहीं है, यह विदेश विभाग ही बता सकता है कि क्या बातचीत हुई है।

Bridges on National Highways in Uttar Pradesh

*162. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of bridges constructed on National Highways in Uttar Pradesh during the last three years;

(b) the number of bridges proposed to be constructed during the current year together with the details thereof; and

(c) the target proposed to be fixed for construction of bridges during the Ninth Five Year Plan?

MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) Five number of bridges were constructed on National Highways in Uttar Pradesh during the last three years.

(b) Five bridges are targetted to be completed during the current yer (1996-97). The details thereof are as under:—

(1) Bridge over Sarain river on Sitapur bypass on NH-24.

(2) Khajuri bridge in Km. 70 of NH-29.

(3) Maghai bridge in Km. 88 of NH-29.

(4) Ami bridge in Km. 188/2 of NH-29.

(5) Taraina bridge in km. 165 of NH-29.

(c) The 9th Five Year Plan is yet to be finalised.

श्रीमती मालती शर्मा: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के भाग "ग" के उत्तर में मैं यह पूछना चाहती हूं कि नवी पंचवर्षीय योजना में क्या दिल्ली से हरिद्वार तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कोई योजना है? दूसरा, स्टेट हाईवेज़ में भी क्या यह योजना है कि पानीपत से खटीमा मार्ग जो तितावी शुगर मिल के पास से होकर गुजरता है, वहां हिंडन नदी का एक पुल है जिस पुल के ऊपर विभाग ने एक बोर्ड लगा दिया है कि इससे अधिक भार इस पुल के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए? लेकिन एक तो वह पुल सिंगल है और उसके नीचे के तमाम वैल्डर कट चुके हैं। एक बार वहां दुर्घटना हो चुकी है और भविष्य में भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है जब कि तितावी शुगर मिल का सारा गन्ना वहां से गुजरता है और हरियाणा को जाने वाला पूरा ट्रैफिक भी वहां से गुजरता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि केन्द्र की सरकार जो दो वर्ष से उत्तर प्रदेश में है, क्या इस मार्ग और इस पुल की तरफ तुरन्त ध्यान देकर आप यह बताएंगे कि नवीं पंचवर्षीय योजना में इसके निर्माण की कोई योजना आपके पास है?

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, generally, so far as declaration of the highways is concerned, we have not declared any highways because of financial crunch. After the budgetary allocation I find that there is some relief. I will think over, consider the project which the hon. Member has mentioned.

With regard to the Delhi-Hardwar State highway, it is with the State. Therefore, the State Government has to take care of it. I will also take into consideration the bridge at Panipat, which the hon. Member has mentioned.

श्रीमती मालती शर्मा: एक प्रश्न जो इसी का महत्वपूर्ण भाग एक था कि दिल्ली से हरिद्वार तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बात है इसका उत्तर मैं मंत्री जी से चाहती हूं। कुम्भ मेला आने वाला है और इस रास्ते

की भारी दुदर्शा है। मान्यवर, एक तो इसके बारे में माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है जिसके संबंध में, मैं आपसे जानकारी चाहती हूं कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर भारी संख्या में एनक्रोचमेंट है और उसके कारण सड़के बहुत छोटी पड़ गई है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इन मार्गों की दिक्कतों को कम करने के लिए आपने सड़कों के निर्माण की कोई योजना बनाई है? और आपने कितना पैसा पिछले दो वर्षों में इन हाईवेज पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर या जो प्रान्तीय राजमार्ग हैं उन पर खर्च किया है? उत्तर प्रदेश की हालत के बारे में लोगों का कहना है कि गड्ढों में सड़के हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, यह पता नहीं लगता है। इतनी दुर्दशा उत्तर प्रदेश की सड़कों की है। इसलिए इन मार्गो के विषय में, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आप नेशनल हाईवेज के बजाय ये जो स्टेट हाईवेज हैं इनकी दुदर्शा की तरफ भी ध्यान देंगे विशेष रूप से दिल्ली से हरिद्वार तक की सड़क के विषय में इस योजना में इसे नेशनल हाईवेज घोषित करने का क्या आपका विचार है?

SHRI T. G. VENKATRAMAN: Sir, as I have already pointed out, we cannot, at present, take any State highway into national highways. Only after this Budget allocation has been made, there is some relief. I will think about the road which the hon. Member has mentioned.

With regard to removal of encroachments, as and when they are reported, we are taking action for their removal.

Regarding allocation for U.P., we have allotted Rs. 3,900 lakhs. The expenditure out of the external funding is Rs. 3,710 lakhs. This amount has been spent in the year for which the hon. Member has asked this.

Regarding declaration, we can decide only after this. We have to take into consideration whether it comes in the norm and all those things. Then we will decide about it.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: सभापति जी, सरकार ने फाइनेंशियल कंसट्रेंट्स की बात कही है और फाइनेंशियल कंसट्रेंट्स को मीट करने के लिए उन्होंने बीओटी स्कीम बनाई है। क्या उत्तर प्रदेश की इन सड़कों को सुधारने के लिए, पुलों को बनाने के लिए और नई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए बीओटी स्कीम के अन्तर्गत किसी विदेशी या अपने ही देश के किसी पूंजी लगाने वाले व्यक्ति से इस संबंध में बात हो रही है? और अगर हो रही है तो उसका ब्यौरा क्या है?

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, regarding declaration of national highways, I have given the answer earlier. The same answer will hold good for this question put by the hon. Member.

With regard to the BOT scheme, wherever the State Government asks for taking up a road under the scheme, we take it into consideration, and we put it on global tender.

श्री राजनाथ सिंह: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या भूतल परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले सारे नेशनल हाईवेज का ऐसा कोई सर्वे कराया है जिससे इस बात की जानकारी मिल सके कि नेशनल हाईवेज पर कितने ब्रिजेज की आवश्यकता है, कितने पुलों की आवश्यकता है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे ब्रिजेज का निर्माण नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा कर लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है? यदि है तो कब तक और यदि नहीं है तो उसका कारण क्या है? महोदय, साथ ही मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जब भी हम नेशनल हाई-वेज से गुजरते हैं और रास्ते में जो भी ब्रिज आते हैं, वहां पर साइन बोर्ड लिखा होता है कि खतरा है, धीरे चलिए, पुल कमजोर है। तो क्या भारत सरकार ने इसका भी सर्वे कराया है कि नेशनल हाई वेज में जितने भी ब्रिजेज आते हैं उनमें कितने ऐसे ब्रिजेज हैं जिनकी लाइफ समाप्त हो गई है और ऐसे ब्रिजेज का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है?

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, Uttar Pradesh is served by twelve number of national highways viz. Nos. 2, 3, 7, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 56. The total length of these national highways is 2,741 kilometres, excluding the length of urban links passing through the municipal limits.

Sir, about the broad bridges on the national highways, there is a long list. I will provide it to the hon. Member.

With regard to the survey which the hon. Member has suggested, as and when

it is reported by the State Government, we take speedy steps.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: सभापति महोदय, आपको बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितना टारगेट ब्रिजेज बनाने का या पुल बनाने का था और क्या आपने यह आंकलन किया है कि उनमें से कितने पुल बन सके हैं या अभी अधूरे हैं और कितने बनाने के लिए बाकी है? मेरे प्रश्न का भाग "ब" यह है कि राज्य सरकार के अधिकारियों से क्या कभी आपने बातचीत की है कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं या संयुक्त रूप से इस कठिनाई के निराकरण के लिए आपने क्या सोचा है?

SHTI T.G. VENKATRAMAN: Sir, the question is of a general nature and I could not understand what actually he is asking. He has asked a question with regard to the entire region. Therefore, I need a separate notice.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, my clearcut question is whether any assessment has been made, how many bridges were completed during the Eighth Five-Year Plan out of the number of bridges targeted and how many of them are incomplete? Did the Minister or his Ministry consult the U.P. Government and the Officers of the U.P. Government from time to time as to what difficulties they had and what special steps were taken to solve those problems. This is a simple and specific question. If this is not a specific question, what else is a specific question? I am asking about his assessment during the Eighth Five-Year Plan. An assessment of the Eighth Five-Year Plan will form the basis of the Ninth Five-Year Plan.

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, I will submit a detailed answer to my learned friend. During 1992-97, we sanctioned a total amount of Rs. 12,799 lakhs. The work has been going on on the basis of the allotted amount.

With regard to the statistics about each region, I have not received any report from the State Government. As and when a report comes, we will take care of it.

MR. CHAIRMAN: Question No. 163. Hon. Member is absent.

*163. [*The questioner (Shri Sanjay Dalmia) was absent. For answer, vide cols ... infra*].

Textile export growth in 1996-97

*164. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the ovrall growth in textile exports during 1996-97 especially in cotton yarn and woollens; and

(b) the action proposed to improve quality in fabric production and restructuring technology especially for garment sector?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to provisional figures available with the Ministry of Textiles, the overall textile export growth in dollar terms during 1996-97 (upto January, 1997) is 9.9% and in terms of rupees 17.9%. The growth in respect of cotton yarn is 47.5% in terms of dollars and 58.3% in terms of rupees in 96-97. Similarly, the growth in the wool and woollen exports is 44.4% in dollar terms and 54.9% in rupee terms in 1996-97.

(b) The following measures are being taken to improve the quality in fabric production and technological upgradation of garment sector:

(i) The customs duty on the textile machinery was reduced from 25% to 10% in the year 1996-97 and in the present budget i.e. 1997-98, it was proposed to add some more processing machines to this category. This would help the industry to produce high quality fabric. Further in the present budget, it was also proposed to reduce customs duty from 40% to 30% on